भारत - बाँग्लादेश संबंध

(India - Bangladesh Relations)

भारत के पूरब में स्थित बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। यह पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तानी सरकार के तानाशाही रवैये के कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को दमन का शिकार होना पड़ा। दमन से शिकार हुए बांग्ला देशियों ने भारत में आकर शरण लेने लगा जिसके कारण भारत की राजनीति बेपटरी हो लगा, तब मजबूरन भारत को सैन्य हस्तक्षेप करना पड़ा। जब 3 दिसम्बर 1971 को पाकिस्तान ने पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, आगरा और श्रीनगर पर बमबारी कर युद्ध छेड़ दिया तब दो सप्ताह की लड़ाई के बाद बाँग्लादेश की मुक्तिवाहिनी और भारतीय सेना के समक्ष 16 Dec 1971 को बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के कमाण्डर जनरल नियाजी ने सरेण्डर होकर हथियार डाल दिए। भारतीय प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी और अन्तर्राष्ट्रीय जगत के सम्मिलित प्रयासों द्वारा 17 Dec 1971 को बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम देश है लेकिन यह आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है। सर्वप्रथम भारत ने बाँग्लादेश को भारी मात्रा में अन्न देकर कम से कम 50 लाख लोगों को भूख के कारण मौत के मुँह में जाने से बचाया। रेलवे, जल, परिवहन, परमाणु ऊर्जा, रक्षा तथा डाक-व्यवस्था के क्षेत्र में दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश वासी भारत को 'बड़े भाई' की भूमिका में देखते हैं।

शेख मुजीब जो पाकिस्तान के जेलों में नजरबंद था, भारत के प्रयासों से इन्हें पाकिस्तानी जेल से रिहा कराया गया और 10 जनवरी 1972 को भारत पहुँचने पर अपना आभार प्रकट करते हुए कहा कि "भारत ने जो हमें किया है वह कभी भुलाने लायक नहीं है।" 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के बीच एक 25 वर्षीय मैत्री संधि हुई जिसमें आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने, एक दूसरे की सीमाओं का आदर करने, एक दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश की सहायता नहीं करने, विश्व शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करने का संकल्प लिया गया तथा यह भी हुआ कि अगर दोनों देशों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाए तो दोनों मिलकर आपसी बातचीत द्वारा उसका समाधान करेगा किसी अन्य देशों का हस्तक्षेप नहीं होगा।

व्यापार समझौता के तहत सीमाओं के दोनों तरफ 16-16 K.M तक स्वतंत्र व्यापार की व्यवस्था की गई। आर्थिक क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये मूल्य का माल और सेवाएँ प्रदान [illegible] के साथ ही साथ 50 लाख पौंड की विदेशी मुद्रा का

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

ऋण देने का भी एलान किया। अप्रैल 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में सभी बंद पाकिस्तानी युद्धबंदी को छोड़ दिए गए। भारत बाँग्लादेश के बीच मई 1974 में सीमांकन समझौता हुआ जिसमें यह निर्णय हुआ कि भारत 187 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा क्षेत्र बाँग्लादेश को देगा जिससे बाँग्लादेश को दाहाग्राम और अंगारपोटा के लोग अपने इलाके तक आसानी से आ-जा सके। मई 1974 में भारत ने बांग्लादेश को 40 करोड़ रुपये का कर्ज दिया, उस रुपये को रेल के डिब्बे, उपकरण, सीमेंट, मशीनें तथा कृषि उपकरण खरीदने में बांग्लादेश लगाया।

15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के कुछ सैनिक अधिकारियों द्वारा शेख मुजीब और उनके सहयोगियों की हत्या कर शासन अपने हाथ में ले ली तब भारत और बांग्लादेश के संबंध में खटापन आ गया। जो सरकार बनी उसके भारत के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक ही रहा। जनवरी 1976 में बांग्लादेश का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया और यह तय हुआ कि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद फरक्का जैसे प्रश्नों की आड़ में बांग्लादेश के द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार अभियान चलाया गया।

कोलकाता बंदरगाह को बंद होने से बचाने के लिए फरक्का बाँध आवश्यक था। कोलकाता भारत का औद्योगिक केन्द्र है। इसलिए फरक्का बाँध को बचाने के लिए समझौता हुआ। फरक्का बाँध और उसकी सहायक नहर को अप्रैल 1975 में बाँग्लादेश के साथ समझौता होने के बाद चालू किया गया परन्तु कुछ मतभेदों के कारण उस दिशा में प्रगति नहीं हो सकी। इस प्रकार दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध बांग्लादेश की मुक्ति के पाँच साल के भीतर ही खराब हो गए।

बांग्लादेश और भारत के बीच 20 sep 1977 को एक समझौता किया, जिसे फरक्का समझौता कहा जाता है। फरक्का समझौता 5 नवम्बर 1977 को लागू किया गया, जिसमें दो व्यवस्थाएँ की गई - (i) अल्पकालीन व्यवस्था (Short term provision): इस व्यवस्था के अन्तर्गत 12 अप्रैल 1982 तक भारत को 20,800 क्यूसेक और बांग्लादेश को 34,700 क्यूसेक पानी मिलने की बात कही गई। इसी अवधि में पानी की बहुत कमी रहती है। इस अवधि के शीघ्र बाद भारत को मिलनेवाली पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी और जल्दी ही 40,000 क्यूसेक तक पहुँच जाएगी। यह भी कही गई कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत फरक्का के नीचे से भी कुछ मात्रा में पानी ले सकता है। यह व्यवस्था 5 वर्ष के लिए की गई और 3 वर्ष बाद इस पर पुनर्विचार करने की बात कही गई।

(ii) दीर्घकालीन व्यवस्था (Long term Arragements) - इसके अन्तर्गत भारत और बांग्लादेश दोनों ने अपने ऊपर गंगा के प्रवाह को तेज करने की जिम्मेवारी ली। लेकिन यह प्रयास निष्फल रहा। [illegible] इस समझौते को लेकर तीखी प्रतिक्रिया हुई। यह बात कही [illegible] कि गंगा [illegible] नदी है, क्योंकि इसकी 80% धारा भारत में है। 40,000

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

क्यूसेक से कम पानी मिलने पर कोलकाता की स्थिति खराब हो सकती थी, क्योंकि फरक्का बाँध का निर्माण कोलकाता के लिए ही हुआ था। पानी की कमी के दौरान भारत को सिर्फ 20,800 क्यूसेक पानी मिलता था जो कि भारत की आवश्यकता से 20,000 क्यूसेक कम था यदि कहा जाए कि बंगाल और त्रिपुरा की जनता को नाराज करके फरक्का समझौता हुआ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इस तरह 1982 में इस समझौते को रद्द कर दिया गया। समझौते के समय भारत की मान्यता थी कि गंगा के प्रवाह को तेज किया जा सकेगा। बांग्लादेश ने नेपाल, चीन, भूटान तथा विश्व बैंक को भी इस समस्या में घसीटने का प्रयास किया। इस तरह कुछ और भी समस्या हैं जैसे अल्पसंख्यकों की समस्या - आज भी बंगलादेश में हिन्दू और बिहारी मुसलमान अपने को असुरक्षित महसूस करते हो जिसके कारण उनका अवैध रूप से भारत में आना जारी है। जिसके कारण त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम की स्थिति असंतुलित हो गई हो

मुहरी नदी सीमा विवाद :- 1974 के समझौते के अनुसार मुहरी नदी के पानी की मध्यधारा ही भारत बंगलादेश की सीमा रेखा है। लेकिन 1979 में बांग्लादेश रायफल्स ने इस समझौते का उल्लंघन करके जमीन पर दावा किया। यह विवाद 44-45 एकड़ (24 हेक्टेयर) जमीन के संबंध में है। यह जगह त्रिपुरा राज्य के बेलोनिया कस्बे के पास मुहरी नदी के भारतीय तट पर स्थित है।

न्यू मूरे द्वीप विवाद (Dispute of New moore Island) :- बंगाल की खाड़ी में उभरा यह एक नया द्वीप था जिसका क्षेत्रफल 2500 वर्ग मीटर था। बांग्लादेश इसे 'दक्षिण तलपत्ती' कहता है तथा भारत इसे 'पुरबासा' की संज्ञा देता है। यद्यपि यह द्वीप भारतीय सीमा में है, फिर भी बांग्लादेश इस पर अपना दावा करता रहा है। अगस्त 1981 में बांग्लादेश के आठ युद्धपोतों ने इस द्वीप पर कब्जा करने का विफल प्रयास किया।

चकमा शरणार्थी समस्या (Problem of Chakama refugees) - चकमा शरणार्थियों की समस्या ने भी दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न कर दी है। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश ने 'चकमा' शरणार्थियों को वापस लेने का भारत से वादा किया था, किन्तु अधिकांश चकमा शरणार्थी बांग्लादेश लौटना नहीं चाहते।

अप्रैल 1982 में जनरल इरशाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। बंगलादेश भारत संबंधों में व्यापक सुधार हुआ। अक्टूबर 1982 में भारत की मांग की और 1977 के दोनों देशों के बीच संपन्न समझौते को रद्द किया गया। अध्ययनोपरान्त 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों में तीस्ता जल समझौता हुआ। भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई शेष पानी किसी को आवंटित नहीं किया गया। फरक्का में गंगा नदी के जल बँटवारे पर दोनों देशों के बीच हुई सहमति के समझौते पर 22 नवम्बर 1985 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। अगस्त 1986 में ढाका में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन (सार्क) का आयोजन किया गया।

तीन बीघा गलियारा - तीन बीघा गलियारा 26 जून 1992 को भारत ने बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया। 178 मीटर लम्बा तथा 85 मीटर चौड़ा तीन बीघा गलियारा

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

एक ऐसा क्षेत्र है जो भारतीय क्षेत्र 'कुचलिबाड़ी' को शेष भारत से जोड़ता है, क्योंकि इसके तीन तरफ बाँग्लादेश का राज्य क्षेत्र है। भारत में कुचलिबाड़ी क्षेत्र के निवासी तीन बीघा से होकर भारत के मूल भाग में आते जाते थे तथा बाँग्लादेश के दाहग्राम तथा अंगारपोटा के लोग घूमकर काफी दूरी तय करके बाँग्लादेश के मूल भाग में जाते थे। इससे उन्हें परेशानी के साथ-साथ अधिक समय भी देना पड़ता था। तीन बीघा क्षेत्र को 999 साल के पट्टे पर देने का भारत के कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया। उल्लेखनीय है कि इस 'तीन बीघा' जमीन के लिए दोनों देशों के बीच काफी लम्बे अरसे से तनाव था।

अगरतल्ला समझौता :- (Agartala Agreement 9 March 1997) त्रिपुरा में लगभग 11 वर्षों से रह रहे 50 हजार से अधिक चकमा शरणार्थियों की बाँग्लादेश वापसी के लिए भारत और बाँग्लादेश के बीच 9 March 1997 को अगरतल्ला में एक समझौता हुआ।

कोलकाता-ढाका बस सेवा :- जून 1999 में भारत की पहल पर कोलकाता ढाका बस सेवा प्रारंभ की गई। कोलकाता से ढाका पहुँचने वाली पहली बस के स्वागत के लिए स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ढाका पहुँचे। इसके अलावे दोनों देशों के बीच निम्नलिखित सुविधाओं का आदान-प्रदान हुआ।

भारत और बाँग्लादेश के बीच यात्री रेलगाड़ी सेवा प्रारंभ :- जुलाई 2001 में दोनों देशों के बीच यात्री रेलगाड़ी सेवा प्रारंभ करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। आरक्षित सीटों वाली इस सुल्तान एक्सप्रेस गाड़ी को सियालदह एवं बंगबंधु स्टेशनों के बीच चलाने का निर्णय लिया गया।

दोनों देशों के बीच अगरतल्ला ढाका बस सेवा 19 सितम्बर 2003, आतंकवाद एवं तस्करी संबंधी मामलों पर समझौता 9 जनवरी 2004, प्रयोगशालाओं (खाद्य, कृषि उत्पादों, कपड़े इत्यादि की जाँच) को मान्यता 23 मार्च 2004, सीमा विवाद के संदर्भ में (सीमा पर अपराध रोकने सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग) समझौता मई 2004, द्विवार्षिक सीमा समन्वय बैठक (सीमा पर अपराध, अवैध घुसपैठ, हथियारों तथा जानवरों की तस्करी रोकने के लिए) सम्पन्न 2-3 अगस्त 2004, भारत-बाँग्लादेश एवं म्यांमार के बीच प्राकृतिक गैस आपूर्ति संबंधी समझौता - 13 जनवरी 2005 (इसके लाभ से तीनों देशों के समुद्री क्षेत्रों में गैस भंडार ढूँढने का काम प्रारंभ)।

बेगम खालिदा जिया की भारत यात्रा - 20 मार्च 2006 को बाँग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया तीन दिवसीय यात्रा पर भारत आई। भारतीय प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह से बातचीत के क्रम में स्वीकार किया कि दोनों ही देश आतंकवाद के शिकार हैं। इनसे निपटने के लिए दोनों को मिलकर संघर्ष करना चाहिए। दोनों देशों के बीच दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए :- (i) द्विपक्षीय व्यापार संवर्द्धन एवं (ii) नशीले पदार्थों [illegible] पर रोक।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

शेख हसीना की सत्ता में वापसी (Sheikh Hassina's return to power)

बांग्लादेश के जन्म में सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले भारत के लिए आवामी लीग का 29 Dec 2008 को सम्पन्न आम चुनाव में विजयी प्राप्त शेख मुजीबुर्रहमान की पुत्री शेख हसीना की छवि धर्मनिरपेक्ष है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में भारत के विरुद्ध बांग्लादेश की भूमि का इस्तेमाल आतंकवादियों को नहीं करने दिया जायेगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर में सक्रिय सभी आतंकवादियों के कैंप बांग्लादेश में हैं। उन्हें हथियारों की आपूर्ति भी बांग्लादेश से होती रही है।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत दौरा 10 जनवरी 2010 को डॉ० मनमोहन सिंह के साथ द्विपक्षीय सहयोग के पाँच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए जिसमें आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया, जिससे भारत को बहुत राहत मिली। 2012 तक दोनों देशों के बीच 130 K.M लम्बी ट्रांसमिशन लाईन डालने का भी निर्णय लिया गया था। बांग्लादेश के आर्थिक विकास के लिए एक अरब डालर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी। शेख हसीना की भारत यात्रा ऐतिहासिक रही। उन्हें इंदिरा गाँधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया और उनके साथ भारत ने ऐसे समझौते किए जो उन्हें मुल्क में राजनीतिक मजबूती देंगे

प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा – 6-7 sep 2011 को एक उच्चस्तरीय शिष्टमंडल के साथ प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह ने 6-7 सितम्बर 2011 को बांग्लादेश की यात्रा की जिसमें निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर हुए – (i) द्विपक्षीय सहयोग हेतु व्यापक फ्रेमवर्क, (ii) सीमा प्रोटोकॉल, (iii) नवीकरणीय ऊर्जा तथा (iv) सुन्दरवन संरक्षण समझौता शामिल है

भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सत्ता सँभालने के बाद भारतीय विदेश मंत्री श्रीमति सुषमा स्वराज ने जून 2014 में बांग्लादेश के साथ सम्बन्धों को सकारात्मक दिशा देते हुए 'मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन' की आवृत्ति (फेरा) बढ़ाने, ढाका से गुवाहाटी और शिलांग तक बस सेवा आरंभ करने, बांग्लादेश को त्रिपुरा से 100 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने तथा वहाँ एक विशेष आर्थिक जोन के विकास करने की घोषणा की। इस दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री श्री अबुल हसन महमूद अली ने कहा था – " बांग्लादेश भारत का नम्बर one (01) मित्र बनना चाहता है और देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने और ऑटो मोबाइल, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारतीय कम्पनियों को आमंत्रित

करता है।" आनेवाले समय में दोनों देशों के बीच सम्बन्ध निश्चित तौर पर बेहतर ही होंगे। इतना ही नहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014 में ही कोलकता में 'नजरूल तीर्थ सेन्टर' का उद्घाटन किया। यह सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सेन्टर के रूप में खोला गया और कहा गया कि भारत एवं बाँग्लादेश के मध्य इससे साँस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2016 में मोदी सरकार के अथक प्रयासों से भारत बाँग्लादेश सीमा विवाद को सुलझा लिया गया। इसके लिए भारत को अपने संविधान में 100 वाँ संशोधन करना पड़ा।

निष्कर्षतः भारत और बाँग्लादेश के मध्य और मधुर संबंध बनाने की दिशा में नए कदम भी उठाए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2017 में दोनों देशों में सहमति बनी है। आवागमन को और बढ़ावा देने हेतु नवम्बर 2017 में भारत और बाँग्लादेश के मध्य 'बन्धन एक्सप्रेस' का परिचालन शुरू किया गया। इस प्रकार दोनों देशों के बीच सम्बन्ध मधुर होने से भारत एवं बाँग्ला देश में नवीन सांस्कृतिक हब स्थापित होगा। भारत द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भी बाँग्लादेश को भरपूर सहायता प्रदान की जा रही है ताकि भारत की 'प्रथम पड़ोसी' नीति को बढ़ावा मिल सके और बाँग्लादेश में अमन-चैन बना रहे ताकि भारत भी हर पैमाने पर चैन की वंशी बजाते रहें।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष- राजनीति विज्ञान
डी०के० कालेज, डुमराँव
दिनांक - 18/05/2020

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA